

छोटे स्वास्थ्य केंद्र होंगे डिजिटल

■ नड्डा करेंगे ई-सुश्रुत क्लीनिक का शुभारंभ ■ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी कई डिजिटल सुविधाएं

नई दिल्ली, 27 जून. देश में छोटे क्लीनिकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डिजिटलीकरण को नई गति मिलने जा रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को ई-सुश्रुत क्लीनिक का शुभारंभ करेंगे.

यह सी-डैक द्वारा विकसित एक हल्का, किफायती और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सक्षम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से छोटे आउट पेशेंट क्लीनिकों के लिए तैयार किया गया है. देश के अनेक छोटे क्लीनिक अब भी मरीजों के पंजीकरण, बिलिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे कार्य मैनुअल तरीके से करते हैं. बड़े हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम उनके लिए महंगे और जटिल साबित होते हैं. इसी चुनौती को देखते हुए सी-डैक ने ई-सुश्रुत क्लीनिक विकसित



किया है, जो सरल, क्लाउड आधारित और कम लागत वाला डिजिटल समाधान उपलब्ध कराएगा. इसे सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों, उप-केंद्रों और निजी क्लीनिकों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. यह प्रणाली मरीजों के पंजीकरण, बिलिंग, एमआईएस रिपोर्टिंग, स्पीच-टू-टेक्स्ट, क्लीनिकल डिस्क्रिप्शन सपोर्ट सिस्टम, एबीएचए खोज, स्कैन एंड शेयर जैसी एबीडीएम सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी.

सल्लिडी को लेकर सियासी घमासान

जयपुर 27 जून.केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को खीरे की खेती (पॉलीहाउस) के लिए करीब 99 लाख रुपये की सल्लिडी मिलने के मामले ने राजस्थान की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर

राजस्थान में भागीरथ चौधरी को 88 लाख की मिली सल्लिडी चौधरी स्वयं कृषि राज्य मंत्री और बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं

दिया है. आरोप है कि यह सल्लिडी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजना के तहत मंजूर की गई, जबकि चौधरी स्वयं कृषि राज्य मंत्री हैं और पदेन रूप से उस बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं.

इसी कारण विपक्ष ने इसे 'हितों का टकराव' बताते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं.मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद



विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मामला न केवल नैतिकता से जुड़ा है, बल्कि इसमें किसानों के हक और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग का सवाल भी शामिल है.

यूपी को 10 हजार करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी

लखनऊ .उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी सात जुलाई को कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आ सकते हैं. पुलिस-प्रशासनिक अमले और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संगठन ने संभावित कार्यक्रम को लेकर अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं. इस ऐतिहासिक जनसभा के मंच से प्रधानमंत्री कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. रैली में करीब एक लाख से अधिक लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है. इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पाकिंग की रूपरेखा तैयार की जा रही है. मुख्य सभा स्थल पर जर्मन हैंगर तकनीक से एक भव्य और विशाल वाटरप्रूफ पड़ल का निर्माण कराया जाएगा. प्रधानमंत्री की सुरक्षा और वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में पांच हेलीपैड बनाने की योजना है. एडीएम सिटी आलोक कुमार गुप्ता और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने निराला नगर मैदान का बारीकी से निरीक्षण कर कार्ययोजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही, रेलवे प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि सात जुलाई तक इस मैदान को किसी अन्य आयोजन के लिए आवंटित न किया जाए.



ईधन की बढ़ी कीमतें वापस लें

नई दिल्ली, 27 जून. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जनता से राहत छीनकर वसूली की राजनीति कर रही है.

एक्स पर खरगे ने केन्द्र सरकार से की मांग

खरगे ने शनिवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि जब पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान कच्चा तेल 138

अवैध मदरसे पर फिर चला बुलडोजर

आजमगढ़, 27 जून. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील अंतर्गत मोलनापुर गांव में प्रशासन ने प्राथमिक विद्यालय की सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से पांच कमरों के निर्माण को हटाने हुए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. प्रशासन का कहना है कि भूमि सरकारी रिकॉर्ड में प्राथमिक विद्यालय के नाम दर्ज थी और जांच के बाद निर्माण को अवैध पाया गया. कार्रवाई पूरी होने के बाद जमीन का कब्जा ग्राम प्रधान को सौंप दिया गया. क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. प्रशासन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया राजस्व अभिलेखों और नियमानुसार की गई. उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कई अभियान चलाए गए हैं.

ईरान-अमेरिका तनाव फिर चरम पर दोनों देशों के सैन्य हमलों से बढ़ा टकराव

तेहरान/वॉशिंगटन, 27 जून. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोंपस ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य हमलों के जवाब में क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तटीय क्षेत्रों पर हवाई हमले किए थे, जिसे उसने युद्धविराम समझौते का उल्लंघन बताया.

आईआरजीसी के अनुसार, जबकी कार्रवाई में 'क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती के केंद्रों' पर हमले किए गए हैं. हालांकि, इन हमलों के स्थान, प्रकार या नुकसान को लेकर कोई विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है.ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका की ओर से हमले जारी रहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया और

क्वाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में टुप ने कहा कि उन्हें झोन हमले की जानकारी है, लेकिन अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर कोई विस्तृत खुलासा नहीं किया जाएगा. उन्होंने ईरान की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे अनुचित बताया. सेंटकॉम ने बताया कि उसके विमानों ने ईरान के मिसाइल और झोन भंडारों के साथ-साथ तटीय रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया है. अमेरिकी पक्ष ने दावा किया कि यह हमला सिंगापुर के झड़े वाले जहाज 'ऑर लवली' पर हुए झोन हमले के जवाब में किया गया, जो ओमान के तट के पास हुआ था.अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी बयान साझा करते हुए कहा कि ईरान द्वारा हिंसा की स्थिति में उसे उसी भाषा में जवाब मिलेगा.उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका युद्धविराम समझौते का पालन कर रहा है, लेकिन उल्लंघन का जवाब सख्ती से दिया जाएगा. गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच जून 2026 में युद्धविराम और समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन ताजा घटनाक्रम से यह समझौता फिर से संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय तनाव तेजी से बढ़ रहा है.

अधिक कठोर होगी.इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के मिसाइल, झोन ठिकानों और तटीय रडार पोजिशनों पर हमले की पुष्टि की थी.अमेरिकी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई उस झोन हमले के बाद की गई, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक

मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया था. अमेरिका ने इस घटना को ईरान द्वारा किए गए 'सीजफायर उल्लंघन' का परिणाम बताया है. वहीं ईरान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जहाज उसके अधिकृत मार्ग से बाहर जा रहा था.

गाजा मुद्दे पर सरकार मौन क्यों?

सोनिया गांधी अंग्रेजी दैनिक के लेख पर बोलीं

नई दिल्ली, 27 जून. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि गाजा पर हो रहे हमलों के खिलाफ पूरी दुनिया लगातार आवाज उठा रही है, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे है, जो हैरान करने वाली है।

गांधी के शनिवार को एक अंग्रेजी दैनिक में इस विषय पर प्रकाशित लेख का समर्थन करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की मौजूदा विदेश नीति ने भारत को अपने पारंपरिक सहयोगियों फलस्तीन, ईरान तथा पश्चिम एशिया के देशों से दूर कर दिया है और भारत वैश्विक जनमत से भी अलग-थलग पड़ता जा रहा है. खरगे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि गांधी का लेख मोदी सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि फलस्तीनी भाइयों-बहनों, विशेषकर बच्चों, पर हो रहे हमलों



राहुल गांधी ने भी गांधी के लेख का समर्थन करते हुए कहा कि भारत इस मामले में लगातार रणनीतिक दायरे से खिसकता जा रहा है, जबकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इस मुद्दे पर इजरायल से दूरी बना रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा इतिहास में एक हैरान करने वाले रणनीतिक निर्णय के रूप में दर्ज होगी।

के बीच भारत की चुप्पी न तो नैतिक रूप से उचित है और न ही तर्कसंगत. हमारी राष्ट्रीय भावना फलस्तीन के लोगों के साथ खड़े होने की मांग करती है.

हिंदुओं के मामले पर चुप क्यों रहती है कांग्रेस : भाजपा

सोनिया गांधी के लेख की आलोचना करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस विदेश नीति पर वोट बैंक की राजनीति करती है. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इसके उलट भारत ने गाजा और फलस्तीन के मुद्दे पर कई बार अपना रुख साफ किया है और मानवीय सहायता भी दी है. उन्होंने कहा, समस्या यह है कि कांग्रेस हमेशा विदेश नीति में वोट बैंक को प्राथमिकता देती है और इसीलिए वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्होंने इजरायल के साथ कभी कोई संबंध विकसित नहीं किए. उन्होंने आगे कहा कि पार्टी हमसफेक प्रति सहानुभूति रखती है और इजरायल पर हुए हमलों के बारे में कभी कुछ नहीं कहती. उन्होंने कहा, सोनिया गांधी गाजा में मुसलमानों के लिए आवाज उठाती हैं, रफाह के बारे में दबीर करती हैं लेकिन ढाका में हिंदुओं के मामले पर चुप रहती हैं.

एक नजर में

संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी



चंडीगढ़ . बीते शुक्रवार कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें हरियाणा का नया कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है. वह कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए बीके हरिप्रसाद की जगह लेंगे।

संजय दत्त कांग्रेस के सीनियर लीडर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं. महाराष्ट्र से कांग्रेस की छत्र राजनीति (एमएसयूआइ) के जरिये सक्रिय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया. संजयचंद्र दत्त ने महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्य के रूप में कई कार्यकांदा पूरे किए. संजय सतीशचंद्र दत्त महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ संगठनात्मक नेताओं में गिने जाते हैं. वे लंबे समय तक संगठन और विधान परिषद दोनों स्तरों पर सक्रिय रहे हैं. वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के सह-प्रभारी जैसी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.

हस्तियों के ट्वीट



भारतीय उद्यमी, कंटेंट क्रिएटर, और देश के प्रमुख पॉडकास्टर राज शमानी ने हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक अनुभव को साझा करते हुए कहा कि आपके करियर का सबसे खतरनाक दौर तब आता है जब आप बुनियादी आर्थिक स्थिरता पा लेते हैं. जब आपमें कोई मजबूरी नहीं रहती, तो आपकी आगे बढ़ने की भूख खत्म हो जाती है और आप संतुष्ट होकर रुक जाते हैं.



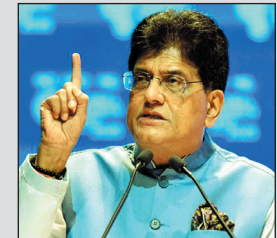
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार से सवाल किया और कहा कि परीक्षाएँ हो या सांकेतिक व्यवस्थाएँ, लगातार सामने आ रही गड़बड़ियाँ गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब केवल नियले स्तर की लापरवाही है और शीर्ष स्तर का इससे कोई लेना-देना नहीं। लेकिन जब ऐसी घटनाएँ बार-बार हों, तो जवाबदेही तय होना भी जरूरी है।

क्षेत्रीय साझेदारियां भारत-ब्रिटेन सीईटीए से व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा: पीयूष गोयल

सीईटीए लागू करने 1,000 सलाहकार तैनात करेंगे

नई दिल्ली, 27 जून. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को देशभर में 1,000 सलाहकार कर्मियों की तैनाती और व्यापार पोर्टल को उन्नत बनाने की घोषणा की, ताकि उद्योग जगत भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते का अधिकतम लाभ उठा सके. उन्होंने कहा कि 15 जुलाई, 2026 से लागू होने वाला यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार एवं निवेश के नए अवसर खोलेगा.

लंदन में आयोजित 10वें वार्षिक ब्रिटेन-भारत सप्ताह के दौरान विभिन्न बैठकों और



कार्यक्रमों में भाग लेते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-ब्रिटेन सीईटीए भारत का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है. उन्होंने बताया कि इससे दोनों देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 अरब जीबीपी की वृद्धि होने का अनुमान है. इंडिया ग्लोबल फोरम कैपिटल फ्रंटियर्स फोरम

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत

भारतीय उच्चायोग और फिक्की द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में पीयूष गोयल ने ब्रिटेन पहुंचे सबसे बड़े और व्यापक भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि सीईटीए के तहत ब्रिटेन में कार्यरत पात्र भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान से पांच वर्ष तक की छूट मिलेगी. इससे वे अपनी बचत को भारत में ब्याज अर्जित करने वाले और कर-मुक्त भविष्य निधि खातों में निवेश कर सकेंगे. गोयल ने उप-राष्ट्रीय आर्थिक साझेदारियों को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए बर्मिंघम-गुजरात और मैनेचेस्टर-महाराष्ट्र संबंधों को वित्तीय के द्विपक्षीय आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया.

को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-ब्रिटेन साझेदारी अब पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं रही. यह प्रौद्योगिकी, संरंभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण खनिज,

रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुकी है. उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की बढ़ती गहराई को दर्शाता है.

आज का इतिहास

- 1975: भारत में आपातकाल के दौरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में केन्द्र ने स्वतंत्रता के बाद सबसे कठोर प्रेस सेंसरशिप लागू किया
- 1981: तेहरान में भीषण बम विस्फोट, इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के 73 पदाधिकारी मारे गये
- 1986: मिजो नेशनल फ्रंट के साथ समझौता, लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने
- 1986: केन्द्र सरकार ने अविवाहित लड़कियों को भी मातृत्व अवकाश देने का कानून बनाया

ऑपरेशन सिंदूर पर फैलाई जा रहीं बातें गलत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर मंत्रालय का बड़ा जवाब

नई दिल्ली 27 जून. रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पिछले वर्ष संसद में दिये गये बयान को लेकर सोशल मीडिया में फैलाये जा रहे विवाद पर शनिवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि इस बारे में कही जा रही बातें जानबूझकर गुमराह करने वाली और तथ्यों के हिसाब से गलत हैं.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए छह सैनिकों के नाम हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किये जाने के बाद सोशल मीडिया पर श्री सिंह के ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सैनिकों की संख्या के बारे में संसद में दिये गये बयान का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाये जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार ने इस जानकारी को छिपाया है।

रक्षा मंत्री पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिए गए भाषण को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। इन पोस्ट में भाषण के एक हिस्से को जानबूझकर चुनकर गलत मतलब निकाला गया है, जैसे कि रक्षा मंत्री ने कहा हो कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। ये बातें जानबूझकर गुमराह करने वाली और तथ्यों के हिसाब से गलत हैं। वक्तव्य में कहा गया है कि जिन लोगों ने रक्षा मंत्री के संसदीय भाषण को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, उन्होंने उनकी बातों व्यापक संदर्भ को जानबूझकर नजरअंदाज किया है। मंत्रालय ने कहा है, मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक खास और जोर-शोर से फैलाई जा रही बात (नैरेटिव) चल रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय पायलट मारे गए थे। यह बात पूरी तरह से गलत थी, फिर भी इसे आक्रामक तरीके से फैलाया जा रहा था ताकि ऑपरेशन की सफलता को कम किया जा सके और जनता का मनोबल गिराया जा सके।

एक करोड़ के मोबाइल के साथ 10 गिरफ्तार

नई दिल्ली, 27 जून. रोहिणी जिला दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने शनिवार को चोरी और छिने गए मोबाइल फोन को तस्करी करने वाले एक बड़े अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया और इस सिलसिले में दो कूरियर संचालकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग एक करोड़ रुपये की कीमत के 325 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, जांच से पता चला कि यह गिरोह चोरी के मोबाइल फोन को दिल्ली से कोलकाता, मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते बंगलादेश भेजता था, जबकि एक अन्य नेटवर्क इन डिवाइस को उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल भेजता था.